



International Journal of Advanced Research in Arts,
Science, Engineering & Management (IJARASEM)

Volume 11, Issue 3, May-June 2024



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

IMPACT FACTOR: 7.583

आधुनिक लोक प्रबंधन एवं लोक कल्याण

अशोक कुमार मीणा

सहायक आचार्य, लोक प्रशासन
राजकीय महाविद्यालय, सांडवा (चूरु)

सारांश

पिछले दो दशकों में तीसरी दुनिया और विकसित देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में सुधारों की मांग को लेकर क्रांति देखी गई है। इसका श्रेय मुख्य रूप से लोक प्रशासन के भीतर कई कारकों को दिया जाता है। इन कारकों में शामिल हैं। खराब गुणवत्ता और अनावश्यक सेवाएं, खराब प्रबंधन, प्रेरणा की कमी, विशेष कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में विफलता और संभावित बाजार/निजी क्षेत्र की उपेक्षा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा हाल ही में किए गए शोध में पाया गया कि निजी क्षेत्र से जुड़े बाजार-प्रकार के तंत्रों से संबंधित नई प्रबंधन प्रथाओं का उपयोग विभिन्न देशों में सार्वजनिक सेवाओं के प्रबंधन में परिवर्तन को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ऐसी प्रथाएँ आधुनिक लोक प्रबंधन का गठन करती हैं (रीनर्ट, 1999)। प्रबंधकीय सुधारों के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र का नवीनीकरण करने के लिए एनपीएम के प्रयास जो महत्व, जनता को दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता और दक्षता के संबंध में बेहतर उत्पादकता पर जोर देते हैं, लोक प्रशासन के दृष्टिकोण में संतोषजनक रूप से फिट नहीं होते हैं। हालांकि इस दृष्टिकोण के कुछ लाभ हैं, और इसलिए यह खोज करने लायक है। इस पत्र का उद्देश्य तीसरी दुनिया और विकसित देशों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए दो नीतियों के संबंध में लोक प्रशासन के लिए आधुनिक लोक प्रबंधन से जुड़े लाभों और समस्याओं का आकलन करना है।

मूल शब्द – आधुनिक लोक प्रबंधन, लोक प्रशासन, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा

आधुनिक लोक प्रबंधन (NPM) :

एनपीएम का तात्पर्य बाजार और व्यावसायिक मूल्यों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रबंधन प्रथाओं को राज्य और अर्थव्यवस्था की नव-उदारवादी अंतर्दृष्टि के अनुसार सार्वजनिक डोमेन में लागू करना है। इस दृष्टिकोण को निजी क्षेत्र से अपनी प्रथाओं को आकर्षित करने के लिए देखा जाता है। एनपीएम की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी और इसकी अवधारणाएँ एंग्लो-अमेरिका से जुड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे कुछ अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठनों द्वारा इसका जोरदार समर्थन किया गया है। इसे 1990 के दशक की शुरुआत में क्रियान्वित किया जाना शुरू हुआ। आधुनिक लोक प्रबंधन सामाजिक विज्ञानों के भीतर नव-शास्त्रीय



आर्थिक साम्राज्यवाद में शामिल है, जिसमें नव-शास्त्रीय आर्थिक प्रथाओं में अधिकांश मुद्दों को संभालने की प्रवृत्ति है।

इस दृष्टिकोण की कई विशेषताएँ हैं। इन विशेषताओं में शामिल हैं अधिकार सौंपना और लचीलापन सुनिश्चित करना, मानव संसाधनों में प्रबंधन को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा और विकल्प बनाना, ग्रहणशील सेवाएँ सुनिश्चित करना, प्रदर्शन नियंत्रण और जवाबदेही, केंद्र में संचालन कार्यों को तीव्र करना, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और विनियमन की गुणवत्ता विकसित करना। ये विशेषताएँ कुछ सामूहिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। निष्पादन प्रणालियों का मूल्यांकन ऐसे लेन-देन के रूप में किया जा सकता है जो सहमत अनुबंधों, सूचना विषमताओं, नैतिक खतरों और अनुरूपता निगरानी चुनौतियों (डोर्नबोस, 2004) पर अधिक जोर देते हैं।

आधुनिक लोक प्रबंधन सुधारों में अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, तकनीकी और संगठनात्मक दृष्टिकोणों से लेकर विभिन्न क्षेत्रों से बहुत अधिक योगदान मिलता है। आर्थिक संकट जिसने एनपीएम की स्थापना की मांग की, उसने उन सुधारों को भी बाध्य किया जो सार्वजनिक सेवाओं को वितरित करने में दक्षता की मांग करते थे। हालाँकि, अधिकांश तीसरी दुनिया के देशों में सार्वजनिक प्रशासन के भीतर सुधार ज्यादातर बाहरी दबावों से प्रभावित होते हैं और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के संदर्भ में बढ़ाए जाते हैं।

आधुनिक लोक प्रबंधन का महत्व :

एनपीएम का मुख्य उद्देश्य राज्य मामलों के प्रशासन में प्रभावशीलता के व्यावसायिक मूल्यों को लागू करना था। एनपीएम की विशेषता व्यावसायिक सिविल सेवा का उन्मूलन, फ्लैट पदानुक्रम, परियोजना प्रबंधन, राजनीतिकरण, कुल गुणवत्ता प्रबंधन, ग्राहकों का उन्मुखीकरण और अनुबंध-आउट जैसे शब्दों से है। आधुनिक लोक प्रबंधन का मुख्य घटक सार्वजनिक सेवा में बाजार के माहौल में पाए जाने वाले प्रदर्शन प्रेरणा और अनुशासन को स्थापित करने या पुनरुपस्थापित करने का प्रयास है। यह आमतौर पर इस धारणा के साथ किया जाता है कि ये प्रथाएं आम जनता के उद्देश्य के लिए बाजार के भीतर दबावों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों को प्रकट करने में दक्षता के संबंध में अनुकूल हैं। इसके अलावा, प्रवृत्ति का प्रस्ताव है कि सरकार संदर्भों में अंतर के बावजूद निजी क्षेत्र से लाभ उठा सकती है। वास्तव में, कई प्रशासनिक कार्य और सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी इस दृष्टिकोण के अधीन रही है। भले ही कई विद्वान आम तौर पर इस बात पर सहमत हैं कि एनपीएम का गठन क्या होता है, वे अक्सर उनकी प्रभावशीलता, मानक और सकारात्मक योगदान (ड्रेचस्लर, 2004) पर भिन्न होते हैं।

एनपीएम में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबंधन का विकेंद्रीकरण शामिल है। 1990 के दशक से, दुनिया भर में एनपीएम नीतियों को अपनाने में वृद्धि हुई है। ऐसी नीतियों में डाउनसाइजिंग, सार्वजनिक सेवाओं के भीतर प्रबंधन विकेंद्रीकरण, कॉन्टैक्टिंग आउट, उपयोगकर्ता शुल्क और साथ ही प्रदर्शन संपर्क शामिल हैं। डाउनसाइजिंग



के साथ-साथ उपयोगकर्ता शुल्क का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, खासकर अफ्रीका में और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों से निकटता से जुड़ा हुआ है। वास्तव में, कुछ देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ स्वतंत्र एजेंसियां शुरू की गई हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पास श्रीलंका और घाना में स्वतंत्र अस्पताल हैं। दूसरी ओर, कॉन्टैक्टिंग आउट और प्रदर्शन संपर्क कई संकटग्रस्त राज्यों में सामान्य नीति विकल्प बन गए हैं। कॉन्टैक्टिंग आउट का उपयोग आमतौर पर राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों में सुधार के एक उपकरण के रूप में किया जाता है, जहाँ वे प्रबंधकों को कुछ प्रकार की परिचालन स्वायत्तता प्रदान करते हैं, जबकि प्रतिबंधों और पुरस्कारों की संरचना के माध्यम से उद्यमों के प्रदर्शन में जवाबदेही को बनाए रखते हैं। हालाँकि एनपीएम प्रथाओं को अपनाकर कई मामलों में लाभदायक रहा है जैसे कि लागत बचत और सड़कों का रखरखाव, फिर भी कई देशों में कुछ एनपीएम प्रथाओं को लागू करने में कई सीमाएँ हैं। ऐसी सीमाएँ विकास, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणालियों, जटिल शासन और अनुबंधों के नेटवर्क के प्रबंधन जैसी स्थितियों में सामने आ सकती हैं (काबुलियन, 1998)।

आधुनिक लोक प्रबंधन के परिणाम :

भले ही एनपीएम ने सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर सुधारों का आह्वान किया हो, लेकिन निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण अंतर को नोटिस करने में कोई मदद नहीं कर सकता है। वास्तव में, एक राज्य मुख्य रूप से अधिकार, बल और दबाव के अपने वर्चस्व के साथ-साथ जनता की भलाई के प्रति अपने उन्मुखीकरण द्वारा प्रतीक है। दूसरी ओर, व्यापार क्षेत्र मुख्य रूप से लाभ अधिकतमीकरण पर अधिक जोर देता है। हालाँकि, एनपीएम जनता से अपने लाभ इकट्ठा करने की प्रवृत्ति के द्वारा सार्वजनिक और निजी हितों के बीच असमानता की उपेक्षा करता है। इस कारण से, सार्वजनिक डोमेन के भीतर व्यावसायिक प्रथाओं का अनुप्रयोग किसी भी दिए गए राष्ट्र की बहुत ही बुनियादी आवश्यकताओं को जटिल बना सकता है, मुख्य रूप से एक लोकतंत्र की नियमितता, समझदारी और उचित विशेषताओं की कानूनी जिम्मेदारी के साथ जो एनपीएम द्वारा जोर दिए गए गति और कम लागत की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं।

वास्तव में, एनपीएम की गति और कम लागत वाली विशिष्टता सीधे एनपीएम के मुख्य उद्देश्य, दक्षता से जुड़ी हुई है, जिसे एनपीएम में संकीर्ण रूप से वर्णित किया गया है, जिससे दृष्टिकोण के पीछे की अस्पष्टता बढ़ जाती है। वास्तविक अर्थों में, दक्षता एक अंतर्दृष्टि है जो पर्यावरण और उपयुक्तता से अत्यधिक प्रभावित होती है। न्यूनतम संसाधनों के साथ आवश्यक प्रभावों को प्राप्त करना बिल्कुल कठिन है। इसी तरह, एक राष्ट्र एनपीएम दक्षता के लिए आवश्यक परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता है जिसे शायद ही परिभाषित किया गया है। दक्षता की अंतर्दृष्टि का यह गलत निर्माण और इसके साथ आने वाला अराजनीतिकरण नौकरशाही और साथ ही तकनीकी तंत्र के विशिष्ट संकेतक हैं, ऐसी विशेषताएं जिनसे एनपीएम मुकाबला करने का प्रस्ताव करता है, जबकि वास्तविक अर्थों में



उन्हें बढ़ावा देता है। नतीजतन, कई राष्ट्र वर्तमान में सार्वजनिक प्रशासन डोमेन और अभ्यास में दक्षता से प्रभावशीलता तक जोर देने के एक आवश्यक समायोजन से गुजर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, समायोजन में चीजों को सस्ते में करने से लेकर अपने उद्देश्यों को अनिवार्य रूप से साकार करने तक का बदलाव शामिल है।

राज्य की भूमिका :

लोक प्रशासन के दृष्टिकोण से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैश्वीकरण राज्य की संरचनाओं के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। हालाँकि, यह उन्हें पुरातन नहीं बनाता है, बल्कि, यह उन्हें पहले से कहीं अधिक अपरिहार्य बनाता है, क्योंकि एक विशेष संरचना या संस्था का निर्माण होना चाहिए और वैश्वीकरण द्वारा बनाई गई सेटिंग को रहने योग्य बनाना चाहिए। वास्तव में, 1989 के बाद से, दुनिया ने राज्य की अविश्वसनीय लचीलापन का अनुभव किया है। हाल के वर्षों में, कई राज्य बने हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण सोवियत संघ और यूगोस्लाविया का विभाजन है, साथ ही यूरोप में चेकोस्लोवाकिया का भी। इस कारण से, हमने ज्यादातर राष्ट्र राज्य के साथ-साथ राज्य के रूप में फिर से उभरने को देखा है (मजमानियन और सबेटियर, 1983)।

इसके अलावा, भले ही यूरोपीय संघ की राज्यता की वैधता के बारे में कुछ जटिल चर्चाएँ हुई हों, लेकिन अगर हम लोक प्रशासन की कार्यात्मक परिभाषा लागू करते हैं, तो हम इसे एक राज्य के रूप में आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। यूरोपीय संघ एक महाद्वीपीय राज्य है जो महाद्वीपीय रेखाओं के साथ संरचित और कार्य करता है। इस कारण से, कुछ संवैधानिक संकट होने के बावजूद, यूरोपीय संघ एक राज्य संरचना है।

इसके अलावा, राज्य उन मुद्दों को संबोधित करने के लिए बेहतर स्थिति में है जो इसे चुनौती देते हैं। ऐसे मुद्दों में संचार और संगठन के तरीके शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान विकास और आर्थिक चिंताएँ जिनमें आधुनिकीकरण, स्थिरता, तकनीकी विशेषज्ञता और विकास शामिल हैं, आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को बढ़ावा देती हैं। शुम्पीटेरियन, नवाचार-आधारित संदर्भ एक कुशल राज्य संस्थान के बिना शायद ही सफल हो सकता है। कार्लोटा पेरेज के तकनीकी-आर्थिक प्रतिमान बदलाव के दृष्टिकोण के मामले में, तो हम अब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के तालमेल की अवधि की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके लिए शक्तिशाली प्रशासनिक क्षमता वाले मुख्य रूप से गतिशील राज्य की आवश्यकता होती है।

सुशासन :

शासन एक तटस्थ अवधारणा है जो नागरिकों, व्यवसाय और समाज के संबंध में राज्य के संबंधों पर अधिक जोर देते हुए किसी दिए गए राजनीतिक व्यवस्था में गतिविधियों को निर्देशित करने पर जोर देती है। हालाँकि, सुशासन शब्द बिल्कुल भी तटस्थ नहीं है, बल्कि एक मानक धारणा है जो एक शक्तिशाली गुणवत्ता निर्णय का

प्रतिनिधित्व करता है जो राज्य के भीतर व्यय में कमी पर जोर देता है और व्यावसायिक मानकों, सिद्धांतों के साथ-साथ हितों का उत्पादन करने के लिए आवश्यक है। सुशासन की अवधारणा तीसरी दुनिया के देशों में अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों के नकारात्मक अनुभवों के परिणामस्वरूप आई। ऐसा ज्यादातर इसलिए था क्योंकि इन संस्थानों का तीसरी दुनिया के देशों पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं था। सुशासन की अवधारणा को रेखांकित करने वाले कई सिद्धांत एनपीएम के समान हैं। इन अवधारणाओं में पारदर्शिता, दक्षता, भागीदारी, जिम्मेदारी और बाजार अर्थव्यवस्था, कानून की स्थिति, लोकतंत्र और न्याय शामिल हैं। भले ही इनमें से अधिकांश सिद्धांत निस्संदेह अच्छे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश संदर्भ पर निर्भर हैं। इस कारण से, तीसरी दुनिया के देशों में कुछ विद्वानों ने सुशासन की अवधारणा को नव-उपनिवेशवादी साम्राज्यवाद के रूप में या असंरचनात्मक वैश्वीकरण के एक घटक के रूप में देखा। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि सुशासन के लिए विकासशील देशों में आर्थिक विकास से पहले संस्थाओं और संरचनाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जबकि विकसित देशों ने आर्थिक विकास के बाद इन संरचनाओं का निर्माण किया। वास्तव में, हम पहले एक ठीक से काम करने वाली सरकार की स्थापना किए बिना सुशासन के साथ-साथ गैर-सरकारी भागीदारी नहीं कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि हमें राज्य की क्षमता को कमजोर नहीं करना चाहिए जो कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट (पीटर्स एंड पियरे, 1998) के तर्क को मात देता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, यह स्पष्ट है कि एनपीएम सुधारों को अपनाने से कई देशों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सुधार एजेंडा जिसने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को अपनाने का संकेत दिया, वह विनियमन, निजीकरण, हस्तांतरण और सरकार के प्रशासनिक कार्यों की अंतिम समाप्ति और उपेक्षा द्वारा चिह्नित था। अंतिम परिणाम में एक अस्थिर और अव्यवस्थित सरकार शामिल थी जो कई चुनौतियों के प्रति संवेदनशील है, जो अभी भी अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी लेती है और जिसकी अखंडता सुधार के साथ-साथ वैचारिक कमी से कमजोर हो गई है। भले ही सरकार और व्यवसाय के बीच कुछ समानताएँ हों, लेकिन सरकार को व्यवसाय की तरह नहीं चलाया जा सकता क्योंकि दोनों क्षेत्र काफी अलग हैं।

References:

1. Doornbos, M. (2004). Good Governance: The Pliability of a Policy Concept. *Frames*, 8, 4, 372-387.
2. Drechsler, W. (2004). Governance, Good Governance, and Government: The Case for Estonian Administrative Capacity. *Frames*, 8, 4, 388-396.
3. Evans, P. and Rauch, J. (1999). Bureaucracy and Growth: A Cross-National Analysis of the Effectiveness of Weberian State Structures on Economic Growth. *American Sociological Review*, 6, 4, 748-765.
4. Fry, R. 1989. *Mastering Public Administration; from Max Weber to Dwight Waldo*. Chatham. New Jersey: Chatham House Publishers, Inc.



5. Kaboolian, L. (1998). The New Public Management: Challenging the boundaries of the Management vs. Administration Debate. and its Critics. *Public Administration Review*, 58, 3,189-193
6. Lynn, L. (1998). The New Public Management: How to Transform a Theme into a Legacy. *Public Administration Review*, 58, 3,231-237.
7. Manning, N. (2005). *The New Public Management and Its Legacy*. Web.
8. Mazamanian, D. and Sabatier, P. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott, Foreman
9. Peters, B.G. and Pierre, J. (1998). Governance without Government? Rethinking Public Administration. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 2,223-243
10. Pollitt, C. & Geert B. (2004). *Public Management Reform. A Comparative Analysis*. Oxford: Oxford University Press.
11. Reinert, E. (1999). The Role of the State in Economic Growth. *Journal of Economic Studies*, 26, 4, 268-326.



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com